THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b) The Jammu and Kashmir Government had proposed an outlay of Rs. 279.46 crores for the Annual Plan 1983-84. But after an assessment of resources and discussions between the State Chief Minister and the Deputy Chairman, Planning Commission, an outlay of Rs. 185 crores for the Annual Plan 1983-84 has been agreed to.

Government Employees and Army men died while on Election Duty in Assam

1154. SHRI F. M. KHAN:
SHRI SYED AHMAD HASHMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total number of Government employees and Army men who lost their lives while on election duty in Assam recently?

(b) what is the total number of dependents of those included in part (a) above who have received compensation and the total amount involved; and

(c) what arrangements, if any, have been made for rehabilitating their dependents and compensating those who received injury?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) No army personnel was deployed on election duty in Assam. None of the employees deputed from outside the State lost his life while on election duty. However, 5 C.R.P.F. and one Rajasthan Armed Constabulary personnel were killed while on duty in Assam. Information in respect of Assam Government employees is being collected from the State Government.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का भरा जाना

1155. **श्री नत्था सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों को भरने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित ऐसे पदों की संख्या जो सीधी भर्ती द्वारा भी भरे जाते हैं तथा उसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तव में भरे गये पदों की संख्या निम्नलिखित है :—

सीधी भर्ती का वर्ष		भारतीय प्रशासनिक सेवा	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1980	आरक्षित	19	9
	भरे गये	19	9
1981	आरक्षित	19	10
	भरे गये	19	9
1982	आरक्षित	22	11
	भरे गये	21	11

तथापि वर्ष 1981 के अनुसूचित जन-जाति के एक उम्मीदवार तथा वर्ष 1982 के अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार के उनके क्रमश: अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के होने के दावों से संबंधित मामलों की संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है । उनके दावों की पुष्टि होते ही उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रस्ताव भेज दिये जायेंगे ।

खाद्यान्न तथा बिजली संबंधी लक्ष्य

1156. **श्री कलराज मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिजली और खाद्यान्न के संबंध में निर्धारित किये गये तथा लक्ष्य पूरे होने के कोई आसार नहीं हैं, यदि हां, तो योजना मंत्री के उस निष्कर्ष का आधार क्या था ; और

(ख) इस संबंध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या साधन जुटाये जाने की योजना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिनांक 8 नवम्बर, 1982 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी सरकार के ध्यान में आई है । अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता की सम्भावित उपलब्धि और वर्ष 1984–85 में विद्युत सृजन से संबंधित अनुमान पहले दो वर्षों 1980–82 में वास्तविक निष्पादन और अगले तीन वर्षों 1982––85 में प्रत्याशित निष्पादन पर आधारित है ।

जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य का संबंध है इस बात पर बल दिया गया है कि छठी योजना के अंत तक 1540 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करना होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो कि अपरिहार्य लक्ष्य है, राज्य सरकार के स्तर तथा जिला स्तर पर दोनों ही स्तरों पर एकजुट प्रयत्न करने होंगें ।

(ख) वार्षिक योजनाओं में संसाधनों के आवंटन में विद्युत क्षेत्रक को बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । स्कीमों की प्रगति का सूक्ष्मता से प्रबोधन करने के लिये उपाय किये गये हैं ताकि समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक हल निकाले जा सकें ।

देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिये कृषि क्षेत्रक को, विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को ऋण देने के लिये संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसके अलावा, वर्षा सिंचित कृषि के लिये अद्यतन शिल्प विज्ञान के उपयोग, उर्वरकों के उपयोग, भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु दशाओं में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग तथा सिंचाई क्षमता के उपयुक्त उपयोग पर भी बल दिया जाता है ।

Blackmarketing by FPS Owners

1157. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Police seized 50 quintals of rationed rice on the 1st February, 1983 on being informed about the black-marketing of the same by some unscrupulous fair price shop owners who were issued the commodity by the Food Corporation of India, Naraina;

(b) if so, what are the details thereof, and how and when the Police came to know of the clandestine activities, where from and from whose possession the rice was recovered and how many people were arrested and vehicles seized in this connection; and